

ओ०पी० सिंह

आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र संख्या: 27 / 2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1-तिलकमार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक: जून 6, 2018 -

विषय: मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका (क्रिमि०) संख्या: 19037/2018 श्रीमती ऊषा जैन व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के तामीला विषयक आदेश दिनांकित 29.05.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

मा० न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का तामीला समय पर न हो पाने अथवा उक्त के सम्बन्ध में समय से आख्या मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न हो पाने के कारण उत्पन्न होने वाली दुरुह स्थिति एवं मा० न्यायालयों द्वारा प्रकट की जाने वाली अप्रसन्नता से आप सभी भली-भाँति अवगत हैं। मा० उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक रिट याचिकायें इसी सम्बन्ध में योजित की जाती हैं, जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने एवं पैरवी करने में राज्य की ऊर्जा एवं संसाधनों का अनावश्यक अपव्यय होता है तथा कभी-कभी उच्चाधिकारीगण को भी मा० न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है।

डीजी परिपत्र सं०-70/15 दि० 20.10.15
डीजी परिपत्र सं०-65/15 दि० 16.09.15
डीजी परिपत्र सं०-60/15 दि० 19.08.15
डीजी पत्र सं०-71/15 दि० 20.10.15
डीजी परिपत्र सं०-58/14 दि० 15.09.14
डीजी परिपत्र सं०-46/14 दि० 06.07.14

आप समस्त के मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु मुख्यालय स्तर से अनेक परिपत्र एवं दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख पार्श्वकित है तथा जो उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट uppolice.gov.in पर उपलब्ध हैं।

3. सन्दर्भित रिट याचिका में मा० न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का तामीला जनरल रूल्स क्रिमिनल के अध्याय-3 एवं मा० उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या: सी.एल. 42/1998 इलाहाबाद दिनांक 20.08.1998 के अनुरूप में सुनिश्चित कराये जाने विषयक, मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2018 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें उल्लिखित परिपत्र संख्या: 42/98 के निर्देश निम्नवत् है :-

C.L.No.42/98 Dated: Allahabad: 20/8/1998

"The Hon'ble court has noticed that the present system of service of summons is not effectively working and service upon the witness/accused persons are not being effected within the period fixed by the courts. The system is effecting the speedy trial of sessions and magisterial cases. In this regard, the court has taken the following decisions for strict compliance by all:-

1. Old practice of fixing one sessions trial for three days in continuation is revived. No other sessions trial except any formal part-heard trial in which one or two formal witnesses are to be examined should be fixed on the that day.
2. The process register as mentioned in rule 12 of chapter III OF G.R.Criminal be strictly maintained by all courts. A police official who is receiving the summons must state his name and number in clear block letters in columns no.5 so that the responsibility be fastened upon him.

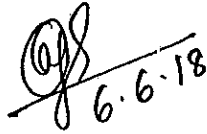
3. Public prosecutor and D.G.C. (Criminal), as the case may be, should be asked to apply to the court for issue of summons but giving complete particulars of the witness. The summons should, thereafter be prepared and served upon the witnesses.
4. **If the police personnel are not complying with the directions of the court then appropriate action under the provision of the contempt of courts Act be initiated against them."**
4. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सन्दर्भित आदेश मे उल्लिखित जनरल रूल्स क्रिमिनल के नियम-12 के प्राविधान निम्नवत् है :

Register of processes - A register of processes shall be maintained in the form given below in all Criminal Courts.

PROCESS REGISTER

Particula of cases	Date of order for issue of process	Date of despatch of process from Court	Description of processer and of the person/ persons to be served	Initial with date of Police or other officials receiving processes	Name of Thana or District to which process sent	Date fixed for return	Actual date of return	Action taken for late receipt of process	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन तथा इस मुख्यालय के सन्दर्भित परिपत्रों में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए मा० न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का तामीला समय से कराकर आख्या मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।


(ओ०पी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद/जी.आर.पी.,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।